

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// अधिसूचना //

क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच (64)

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2018

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफए-3-32/2017/1/पांच(72) दिनांक 21 जुलाई, 2017, में प्रकाशित किया गया था; के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में मद 6 की प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करती है, यथा:-

"स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए 'कारोबार' की अभिव्यक्ति में ऐसा कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार नहीं आएगा जो कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जिसमें कि वे लोक प्राधिकारी के रूप में संलग्न हों, द्वारा किया जा रहा हो"

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(अरुण परमार)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

Government of Madhya Pradesh
Commercial Taxes Department
Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal

Notification

No. FA 3-32/2017/1/V

Bhopal, dated 27 July, 2018

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of this department's notification No. FA-3-32/2017/1/V(41) dated 29th June, 2017, hereby inserts following explanation in the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (3), in item (vi), namely:-

“Explanation. - For the purposes of this item the term ‘business’ shall not include any activity or transaction undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities”

2. This notification shall come into force on the 27th of July, 2018.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh



(ARUN PARMAR)

Deputy Secretary
Govt. of Madhya Pradesh
Commercial Tax Department